THE RICH CULTURAL PAST OF INDIA : CONCERNS AND DEMYSTIFICATION OF REALITIES

भारत का समृद्ध सांस्कृतिक अतीत : चिंताएँ एवं वास्तविकताओं का रहस्योद्घाटन

National Seminar

on

The Rich Cultural Past of India : Concerns and Demystification of Realities

19-20 August, 2023

Organized By:

Department of Sociology,
Sardar Bhagat Singh Govt. P.G. College
Rudrapur (U.S.Nagar), Uttarakhand.
(Affiliated to Kumaun University, Nainital)

Sponsored By:

Indian Council of
Social Science Research

Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi.

VIVEK
PRAKASHAN

Dr. Anchalesh Kumar

20

उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगारी

डॉ0 विकार हसन खाँ *

विकट भौगोलिक संरचना वाले उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्य के रूप में सामने आया है। जबसे उत्तराखंड राज्य अस्तित्व मे आया है, तब से लगातार पहाड़ मे पलायन बड़ता जा रहा है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 09 नवम्बर 2000 को हुयी। राज्य स्थापना के समय आम जनमानस की आवधारणा थी की अलग राज्य होने से इस पर्वतीय क्षेत्र वाले राज्य को सतत विकास का रास्ता मिलेगा, यहां से बेरोजगारी गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन ओर आर्थिक विषमता से मुक्ति मिलेगी, राज्य मे सतत विकास की धारा बहेगी लेंकिन आज राज्य स्थापना के 23 वर्ष पूर्ण हो चुके है लेकिन आज भी राज्य अपनी मूलभूत समस्या को ज्यूं की त्यूं लिये खड़ा है। उत्तराखण्ड 88 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र वाला राज्य है जहां राज्य की लगभग 47 प्रतिशत आबादी निवास करती है, धीरे धीरे पहाड़ के गांव खाली होते जा रहे है, पलायन पहाड़ का सबसे संवेदनशील विषय रहा है। रोजगार पाने के लिये लोग शहरों की ओर पलायन कर रहें है। जिसके कारण गांव विरान होते जा रहे है। सीमित साधनों एवं पूंजी की कमी पर्वतीय क्षेत्रों मे उद्यमशीलता के अवसरो की न्यूवता भी एक कारण है। इसी का परीणाम है कि कृषि क्षेत्रों मे प्रछन्न बेरोजगारी पायी जाती है कृषि यहाँ पर लगभग खत्म होने के कगार पर है क्योंकि कृषि मे बन्दरों गायों ओर जंगली जानवरो (सूअरों) ने पूरी तरह से कृषि को बरबाद कर दिया है, कृषि से लोगों का अब मोह भंग हो चुका है क्योंकि उत्पादन न के बराबर होता है, कभी कभी तो किसान का बिज भी वापस नही आता है पहाड़ में चकबन्दी लागू न हो पाना कृषि के पिछड़ेपन का एक कारण है, कृषि के अतिक्ति आय के अन्य साधन बहुत कम है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 17 सितम्बर 2017 को पलायन की समस्य को जानने के लिये श्री एस0 एस0 नेगी की अध्यक्षता में पलायन आयोग गठन किया गया है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2018 में सरकार को सौंपी पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में हजारों गाँव पूरी तरह खाली हो चुके हैं राज्य में 400 से अधिक गाँव ऐसे हैं जहाँ 10 से भी कम व्यक्ति निवास करते है। पलायन मे अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जनपद शीर्ष पर है अकेले अल्मोड़ा जिले मे ही 70 हजार लोंगों ने पलायन किया, प्रदेश की 646 ग्राम पंचायतों ने 16207 लोग स्थाई रूप से अपना गाँव छोड़ चुके है पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 73 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 5000. रू0 से कम है। आयोग की रिपोर्ट की अनुसार 2011 में उत्तराखंड राज्य में 1034 गाँव खाली थे, वही 2018 तक 1734 गाँव पूरी तरह से खाली हो गये पौड़ी गढ़वाल में 300 से अधिक गाँव खाली हो चुके है, उत्तराखण्ड मे जो जनसंख्या पलायन कर रही है उसमे 42.2 प्रतिशत 26 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवा है युवा रोजी रोटी की तलाश मे सहरों की ओंर जा रहे है पहाड़ मे रोजगार के नाम पर कुछ भी नही है। इसलिये मजबूरी मे इनको शहरों की ओर जाना पड़ता है। रोजगार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, संचार जैसे प्रमुख कारण पलायन के लिये उत्तरदायी है वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना की तुलना करने में पता चलता है कि पलायन की समस्य विकराल रूप धारण करती जा रही है।

* *असिस्टेंट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र विभाग, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर), उत्तराखण्ड ; मोबाईल नं0–9412564034.*

2011 में भारत की जनगणना 121 करोड थी इसमे उत्तराखण्ड राज्य की जनगणना 1116752 थी वर्तमान में भारत की जनगणना लगभग 130 करोड़ से अधिक हो गयी है उत्तराखण्ड राज्य मे 13 जनपद है जिनमे से 10 जनपद पर्वतीय क्षेत्र वाले है इन 10 जनपदो की आबादी केवल 48 लाख 42 हजार रह गयी है। जनगणना 2011 के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के मैदानी जिलो की आबादी 52 लाख 73 हजार है, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जनपद की आबादी लगातार धट रही है जो इस बात का घोतक है कि पलायन की गति तेजी से बढ़ रही है इस प्रक्रिया को समझने हेतु जनगणना 2001 और 2011 की तुलना करने पर हमें निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते है–

जनसंख्या की सारिणी

जिले का नाम	वर्ष 2001	वर्ष 2011
अल्मोड़ा	630567	621927
पिथोरागड़	462289	485993
चम्पावत	224542	259313
बागेश्वर	249462	255984
नैनीताल	762909	955128
उत्तरकाशी	295013	329686
चमौली	370359	391114
रूद्रप्रयाग	227439	236857
टिहरी	604747	616409
पौड़ी गड़वाल	697078	686527
देहरादून	1282143	1698560
हरिद्वार	1447187	1927029
उधम सिंह नगर	1235614	1648367
कुल योग	8489349	10116752

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अल्मोड़ा ओर पौड़ी गढ़वाल की जनसंख्या मे लगातार गिरावट हो रही है इस पलायन का मुख्य कारण बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पेय जल, शिक्षा, स्वास्थ्य जेसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों का नगरों की ओर पलायन तेजी से हेा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों विधान सभाओं का क्षेत्र कम होता जा रहा है ओर मैदानी क्षेत्रों में विधान सभाओं की सीटों की संख्या में तेजी वृद्धि हो रही है। यहां पर यह कहावत चरीतार्थ होती है का पहाड़ का पानी और पहाड़ ही जवानी पहाड़ के काम नही आती है।

पलायन को रोकने के उपाय या सुझाव

उत्तराखण्ड का पर्वतीय क्षेत्र बेरोजगारी अथवा रोजगार के अवसरों के अभाव मे पलायन से सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है जबकि पर्वतीय जनपदो मे पर्यटन उद्योग की अधिक सम्भावनाएँ है यहा पर धार्मिक पर्यटन चार धाम यात्रा, नन्दा देवी राजजात यात्रा, कैलाश मानसरोवर, हेमकुण्ड साहिब, पीराने कलियर, नानकमता आदि विश्व प्रसिद पर्यटन क्षेत्र है यदि इन क्षेत्रों का उचित सुविधांओं से विकास किया जाये तो यहां पर रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सकते है। इसके अतिरिक्त इतिहासिक स्थल यहां पर बड़े मात्रा मे पाये जाते हैं।

विभिन्न प्राकृतिक सुन्दरता से युक्त ग्येशियर, जलप्रपात, मुनस्यारी के बुग्याल आदि पर्यटन के क्षेत्र मे युवाओं को रोजगार देने की क्षमता रखते है इसके लिए आधार भूत संरचना का विकास होना चाहिए। राज्य के पर्वतीय जनपद विभिन्न प्रकार की औषधीय पदार्थों एवं जड़ी–बूटियों से युक्त है जो विभिन्न आर्युवेदिक दवाओं व अन्य उत्पादों को बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होतें है जिसमे प्रमुख रूप से किड़ा जड़ी, शिलाजीत, आंवला, आम दुर्लभ किस्म के फूलों के लिये अनुकूल जलवायु है लेकिन उचित मार्कैटिक (विपणन) सुविधा न होने के कारण पहाड़ी उत्पाद बेकार चले जाते है, राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्र धारचुला, मुन्स्यारी में भेड़ बकरी आदि का पालन करके ऊनी वस्त्र उद्योग का संचालन पूर्वकाल से होता आरा है कृषि के क्षेत्र में चकबन्दी को लागू करके कृषि को आधुनिक रूप दिया जा सकता, सुअरो, बन्दरों गाँव से छुटकारा पाने के लिये सामुहिक खेती सहकारिता को अपनाकर कृषि क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। मशरूम उत्पादन केसर की खेती, रेशम का किड़ा पालकर स्वरोजगार को अपनाया जा सकता है इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह बनाकर ग्राम पंचायत स्तरो पर बनाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रूद्र दत्त के0पी0एस0 सुन्दरम (भारतीय अर्थव्यवस्था) एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 नई दिल्ली
2. ए0पी0 सिंह (भारत मे आर्थिक आायोजन) एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 नई दिल्ली
3. डा0 मामोरिया एवं जैन (भारत की आर्थिक समस्यायें) साहित्य भवन आगरा
4. सांख्यकीय पत्रिका जनपद अल्मोड़ा कार्यालय अर्थ एवं सांख्यकीय कार्य
5. दुबे आर0 एल0 सिन्हा (आर्थिक विकास एवं नियोजन) नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
6. हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण दैनिक समाचार पत्र
7. बद्रीदत्त पाण्डे, उत्तराखण्ड का इतिहास
8. एस0एस0 नेगी पलायन आयोग उत्तराखण्ड रिपोर्ट